

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर
आदेश

एकलपीठ दण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6856/2006

रमेश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक: 16.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री विश्वजीत मंत्री, अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य
श्री नवीन कुमार शर्मा, अधिवक्ता परिवादिया की ओर से.

अभियुक्त - प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत की गयी सामग्री / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त प्रार्थीगण ने जाहिर किया कि इस मामले में अभियुक्त-प्रार्थी रमेश के गिरफ्तार हो जाने की वजह से उसका अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरर्थक हो गया है।

अभियुक्ता- प्रार्थिया शांति देवी की ओर से जाहिर किया उसे इस मामले में झूठा लिप्त किया गया है परिवादिया सीमा तो स्वयं ही नहीं रहना चाहती थी लेकिन समाज के पंचायत के समक्ष परिवादिया सीमा किसी तरह जाने को तैयार हो गयी लेकिन वह पुनः वापिस चली गयी। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त- प्रार्थी रमेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे तथाकथित स्त्रीधन बरामद कर लिया है।

विद्वान लोक अभियोजक व परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि दिनांक 5.9.2006 को परिवादिया सीमा के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया गया तथा उसे गर्म सलाखे से जलाया गया तथा अभियुक्ता-प्रार्थिया शांति देवी भी इस आपराधिक कृत्य में सम्मिलित थी।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया व दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

अभियुक्त-प्रार्थी रमेश का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरर्थक (Infructuous) हो जाने के कारण खारिज किया जाता है।

जहां तक अन्य अभियुक्ता-प्रार्थिया शांति देवी का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्ता-प्रार्थिया की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता, लगाये गये आरोप व दिनांक 6.9.2006 की परिवादिया सीमा की चिकित्सा रिपोर्ट व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में अभियुक्ता-प्रार्थिया शांति देवी को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अभियुक्ता-प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस प्रक्रम पर अधिवक्ता अभियुक्ता-प्रार्थिया ने जाहिर किया कि वह स्वयं को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समर्पण करने के लिए तत्पर है।

इस संदर्भ में इतना ही अंकित किया जाना उपयुक्त होगा कि अभियुक्ता-प्रार्थिया स्वयं को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समर्पित करने के लिए स्वतंत्र है।

यदि अभियुक्ता-प्रार्थिया द्वारा स्वयं को समर्पित कर जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे तो सम्बन्धित न्यायालय, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत ढंग से विचार कर यथा सम्भव उसका शीघ्र निस्तारण कर देंगे।

(न्या० जितेन्द्र राय गोयल)